Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 17-03-2006

Participants : Suman Shri Ramji Lal

an>

Title : Need to improve the functioning of the Gramin Banks in the Country.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गत वर्षों से लगातार खेती के क्षेत्र में ऋण देने की राशि तो बढ़ायी जा रही है किंतु ऋण देने वाली संस्थाओं में तथा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुधार की जो जरूरत है उसके प्रति सरकार बिल्कुल अनदेखी किए हुए है। खेती के लिए कर्जा मुख्य रूप से ग्रामीण बैंकों द्वारा ही दिया जा सकता है। किंतु, खेद है कि सरकार चाहे अनचाहे इन बैंकों की शाखायें कम करती जा रही है। अभी तक 196 संख्या से 152 संख्या तक कम कर दी गयी है। इन ग्रामीण बैंकों द्वारा गत सालों के दौरान 68 हजार करोड रूपये ग्रामीण अंचलों से जमा किया गया है और 35 हजार करोड रूपया वितरित भी किया गया है। इन बैंकों द्वारा ऋण की उगाही 78 प्रतिशत तक है जबकि एनपीए का प्रतिशत मात्र 9 प्रतिशत ही है। सामाजिक दायित्वों को निभाने के बाद भी इन बैंकों का वार्षिक लाभ लगभग 100 करोड रूपया है। इन बैंकों के वर्तमान व्यवस्था के ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत है। 1993 में और 2003 में सरकारी समितियों ने इनमें सुधार की सिफारिशें सरकार को दी थी किंतु अफसोस है कि सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया बल्कि इन बेंकों की शाखायें किसी न किसी रूप से कम अवश्य की है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए अविलम्ब कदम उपरोक्त समितियों के सिफारिशों के आधार पर उठाए जायें और इन बैंकों के कार्यकरण को प्रभावी बनाया जाये।